भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

****

‘चीनी अर्थव्यवस्था का आकलन’ विषय पर पैनल चर्चा की प्रतिलिपि, सप्रू हाउस, 11 दिसंबर 2025

टेशु सिंह : मुझे आप सभी का "चीनी अर्थव्यवस्था का आकलन" विषय पर एक पैनल चर्चा में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जिसकी अध्यक्षता विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक प्रतिष्ठित फेलो और चीन में भारत के पूर्व राजदूत, राजदूत अशोक कांत करेंगे।

सबसे पहले, मैं श्रीमती नूतन कपूर महावर, कार्यवाहक महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारतीय वैश्विक परिषद, से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे अपनी स्वागत टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

नूतन कपूर महावर: धन्यवाद, टेशु। राजदूत कांत, विख्यात विशेषज्ञगण, चीनी अर्थव्यवस्था के आकलन पर आईसीडब्ल्यूए पैनल चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब चीनी आर्थिक विकास से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। चीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने अभूतपूर्व दर से विकास हासिल किया है। फिर भी चीन ऐसा देश नहीं है जिसकी नकल कोई अन्य देश करना चाहे, विशेष रूप से भारत, राजनीतिक या आर्थिक रूप से। उच्च सामाजिक लागत पर प्राप्त आर्थिक विकास न केवल दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं हो सकता, बल्कि यह वांछनीय या अनुकरण करने योग्य भी नहीं है।

हम भारतीय वैश्विक परिषद में मानते हैं कि चीन को अपनी आर्थिक-समाजिक संतुलन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से चीन ऐसा कर सकता है क्योंकि उसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रभाव प्राप्त है। पश्चिमी देशों ने चीन के विकास के मानवाधिकार पहलुओं पर लगातार चिंता जताई है, जो मुख्य रूप से उनकी वैचारिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, लेकिन इससे चीन के आर्थिक विकास की सामाजिक लागतों का महत्व कम नहीं हो जाता।

यह कहते हुए, उस समय जब चीनी अर्थव्यवस्था उच्च विकास का अनुभव कर रही थी, उसकी "अधितप्त" प्रकृति अब धीमी हो रही है। चीन को विनिर्माण के केंद्र के रूप में आकर्षित करने की क्षमता कम हो रही है क्योंकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से व्यवस्थित करने के प्रयास बढ़ रहे हैं। अत्यधिक उत्पादन कम हो गया है, हालांकि विदेशों में डंपिंग नहीं रुकी है, और इसे भी रोकने की जरूरत है। अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ जैसे देश चीनी वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए रखते हैं ताकि स्थानीय उद्योगों और प्रतिस्पर्धा को बचाया जा सके, जो कि अत्यधिक चीनी सरकारी सब्सिडी और अत्यधिक निर्यात-उन्मुख दृष्टिकोण के कारण अन्यायपूर्ण हो सकती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं।

चीन का आर्थिक विकास अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कीमत पर हो रहा है, जो तेजी से अपनी उत्पादन क्षमताओं को खो रहे हैं और बड़े पैमाने पर निर्मित चीनी आयातों पर निर्भर उपभोग अर्थव्यवस्थाओं में बदल रहे हैं, उदाहरण के लिए, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। किसी भी आर्थिक प्रणाली में उत्पादन और उपभोग का संतुलन होना जरूरी है। यह दुनिया

भर में गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है क्योंकि कुछ अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो अधिकांश उत्पादन कर रही हैं। सापेक्ष लाभ या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के सिद्धांत की प्रासंगिकता की अपनी सीमाएं हैं। इसे किसी स्थान पर अत्यधिक उत्पादन की अनुमति देना बाकी स्थानों में आर्थिक विषम परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान के बल पर नहीं दी जा सकती।

इसके अलावा, 'जीवन की गुणवत्ता' की कीमत पर सस्ते श्रम और श्रम-प्रधान मॉडलों की महिमा करना न तो सिद्धांत में और न ही व्यवहार में समझदारी भरा काम है। साथ ही, मुझे पक्का नहीं पता कि हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं या नहीं, जहाँ दुनिया भर में मिलने वाला सारा सामान, सीधे शब्दों में कहें तो, "एक जैसा" हो, जिसमें कोई लोकल इनोवेशन, कोई लोकल डिज़ाइन, कोई लोकल टच न हो, जैसा कि, उदाहरण के लिए, तब होगा जब चीनी सामान को दुनिया के सभी बाज़ारों में भरने की इजाज़त दे दी जाए। 'एकसमानता' पर आधारित दुनिया की अर्थव्यवस्था इंसान होने के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, यह इंसान की अपनी रचनाओं के ज़रिए खुद को व्यक्त करने और पहचान और तारीफ़ पाने की इच्छा के खिलाफ है।

तो, मैंने अभी जो कहा, उसे कौन सा डेटा सपोर्ट करता है? 1980, 90 और 2000 के दशक में चीनी अर्थव्यवस्था लगभग 10% की दर से बढ़ी। 2010 के दशक में, यह लगभग 7.7% की दर से बढ़ी, और अब 2020 के दशक में, विकास दर लगभग 5% है। तो "अधितप्त" हो चुकी चीनी अर्थव्यवस्था "धीमी हो रही है", और 1980 के दशक की तुलना में विकास दर आधी हो गई है। असल में, अब विकास दर डेंग के आर्थिक सुधारों से पहले के समय

जैसी ही हैं। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। कुछ स्वतंत्र विश्लेषण भी हैं जो बताते हैं कि असल में वर्तमान वृद्धि कम हो सकती है, 2024 में यह 2.4% से 2.8% के बीच हो सकती है। और मैं जिन सामाजिक लागतों की बात कर रही हूँ वे क्या हैं?

हम सभी जानते हैं कि "एक-बच्चा" नीति, जो आर्थिक सुधारों से लेकर 2015 तक के समय तक चली, चीन में जनसंख्या और परिवार संरचना को अभी भी प्रभावित कर रही है। एक-बच्चे की नीति का मतलब है बिना किसी वंश के बड़ा होना। इसका मतलब जबरन गर्भपात और नसबंदी भी है। इस मामले में चीन की प्रजनन दर की स्थिति दुनिया में सबसे खराब में से एक है। दूसरा, चीन अब एक घटती और बूढ़ी होती कामकाजी आबादी में बदल रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होने के बजाय सामाजिक सुरक्षा नेट को बेहतर बनाने के बारे में चिंताएं बढ़नी चाहिए।

तीसरा, 1979 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ ही चीन से प्रवासियों का बाहर जाना भी बढ़ा, साथ ही छात्रों और विद्वानों के लिए विदेश में पढ़ाई का चलन बढ़ा और बहुत अमीर एलीट लोगों का दूसरे देशों में जाकर बसना भी बढ़ा। कम प्रजनन दर, बढ़ती उम्र वाली आबादी, बढ़ती प्रवासन दर, पिछड़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा नेट अस्थिर सामाजिक संकेतक पैदा करते हैं। और अस्थिर सामाजिक संकेतक अस्थिर राजनीति पैदा करते हैं।

मुझे यकीन है कि आज हमारी पैनल चर्चा में कुछ ऐसे मुद्दों पर बात होगी। और मैं विचारोत्तेजक चर्चाओं का इंतज़ार कर रही हूँ। और मैं सभी पैनलिस्टों को शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद।

टेशु सिंह: धन्यवाद, मैडम। क्या मैं अब राजदूत अशोक कांत से अनुरोध कर सकती हूँ कि वे कृपया अपने विचार साझा करें और कार्यवाही संचालित करें।

अशोक कांत: धन्यवाद, टेशू। धन्यवाद, नूतन, इस पैनल चर्चा को आयोजित करने के लिए। और एक तरह से, हमारी चर्चा के लिए मंच तैयार करने के लिए, स्पष्ट टिप्पणियाँ पाना बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे मुद्दों पर हल्की-फुल्की चर्चा करना, जो न सिर्फ़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, किसी काम का नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने कुछ ऐसे ज़रूरी मुद्दे उठाए हैं जिन पर चीन के अंदर और बाहर, दोनों जगह ईमानदारी से चर्चा करने की ज़रूरत है।

मैंने मुझे आवंटित पांच मिनट से थोड़ी अधिक समय लेने की अनुमति ली है, क्योंकि मुद्दों को वास्तव में केवल पांच मिनट में संबोधित नहीं किया जा सकता। कल, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा ने चीन के साथ अनुच्छेद 4 पर परामर्श के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो एक तरह से नूतन की बातों से मेल खाती हैं। विकास आंकड़ों के बारे में, मूल रूप से, उसने, जैसे आईएमएफ करता है, बहुत हद तक चीनी अनुमानों का पालन किया। आईएमएफ ने चालू वर्ष के लिए विकास दर को 5% और अगले वर्ष 2025 के लिए 4.5% कर दिया है। हालांकि, जैसा कि नूतन ने बताया, इस डेटा की प्रामाणिकता पर संदेह है। लेकिन उन्होंने तीन और बातें बताईं, जिन पर हमें आज चर्चा करनी चाहिए।

पहला, चीन में घरेलू मांग लगातार कमजोर बनी हुई है, जिसका एक कारण यह है कि प्रॉपर्टी सेक्टर की हालत डांवाडोल है, जैसा कि उन्होंने काफी नरमी से कहा। इससे उपभोक्ता विश्वास कम हुआ है, और यह कमजोर खपत और मुद्रास्फीति-विरोधी दबाव की ओर ले जा रहा है। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु, और उन्होंने इसे असल में काफी मज़बूती से रखा, वह यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते, चीन एक्सपोर्ट से ज़्यादा विकास हासिल करने के लिए बहुत बड़ा है, और एक्सपोर्ट पर निर्यात-आधारित विकास जारी रखने से वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ सकता है। और उन्होंने पाया कि चीन निर्यात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, और उसका बाहरी संतुलन बिगड़ रहा है।

उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्ण सत्र में 15वीं पंचवर्षीय योजना के पीछे के सिद्धांतों पर जो निर्णय लिया गया था, उसका उल्लेख किया। और उन्होंने उल्लेख किया कि चीनी अधिकारियों ने विकास के एक चालक के रूप में खपत बढ़ाने को प्राथमिकता दी है, और अर्थव्यवस्था को वस्तुओं से सेवाओं की ओर पुनः उन्मुख करने के महत्व को मान्यता दी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खपत-प्रधान विकास को चीन के लिए समग्र नीति प्राथमिकता के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है। चीन से वास्तव में कौन से संकेत आ रहे हैं, दोनों नीतिगत घोषणाओं की दृष्टि से और वहाँ हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों के संदर्भ में?

चौथे पूर्ण सत्र में, जो 23 अक्टूबर को समाप्त हुआ, मेरे लिए प्रमुख संदेश यह था कि शी जिनपिंग वास्तविक अर्थव्यवस्था पर जोर दोबारा दे रहे हैं, जो वित्तीय या आभासी अर्थव्यवस्था से अलग है,

उन्नत निर्माण और नवाचार-संचालित विकास पर जोर दे रहे हैं, और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने के लिए स्पष्ट कदम उठा रहे हैं। जब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि चीन पूरे उत्पादन क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है और इसका उत्पादन मान वैश्विक उत्पादन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है, तो आपको यह अनुमान लगाना चाहिए कि यह 2030 तक 45% तक बढ़ सकता है।

कल, मुझे क्यूशी में एक रिपोर्ट मिली, जो पार्टी की पत्रिका है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी जर्नल। शंघाई के एक अधिकारी के इस लेख में यह तर्क दिया गया है कि असल में हम उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। हमें विनिर्माण क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है क्योंकि यह हमारी बड़ी ताकत और भाग्य की सीढ़ी है। और जब शी जिनपिंग असली अर्थव्यवस्था पर ज़ोर देते हैं और अर्थव्यवस्था में विनिर्माण को सही जगह देते हैं, तो उनका यही मतलब होता है।

कुछ दिन पहले जो डेटा आया था, 2025 के पहले 11 महीनों के बारे में, चीन का व्यापार अधिशेष 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया। यह किसी भी देश के लिए पहली बार है जब इस तरह का व्यापार अधिशेष दर्ज किया गया है, भले ही ट्रंप के टैरिफ लगे हों या यह तथ्य कि चीन के निर्यात अमेरिका को लगभग 20% घट गए। तो यह अपने निर्यात को लगातार अन्य देशों में बढ़ा रहा है। चीनी अधिकारियों द्वारा, जिनमें शी जिनपिंग खुद अगुवाई कर रहे हैं, आर्थिक उलझन (इनवॉल्यूशन) को लेकर गंभीर रूप से स्वीकारोक्ति है, जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और अतिरिक्त

क्षमता के कारण चीनी अर्थव्यवस्था में विकृतियों को दर्शाती है, हालांकि वे कभी 'अतिरिक्त क्षमता' शब्द का उपयोग नहीं करते।

लेकिन रोडमैप की बात करें या उठाए गए कदमों की, तो किसी भी विश्वसनीय स्तर का कोई सबूत नजर नहीं आता। हमारे पैनलिस्ट इस पर चर्चा करेंगे। माफ कीजिए, मैं थोड़ा अधिक समय ले रहा हूँ, लेकिन मैं इन मुद्दों को इंगित करना चाहता था। हमारे पैनलिस्ट इस पर गौर करेंगे। क्या चीन के लिए बहुत गंभीर चुनौती बन चुकी उलझन से बाहर निकलने का कोई रोडमैप है? इसे व्यक्तिगत रूप से शी जिनपिंग द्वारा स्वीकार किया गया है। वे घरेलू मांग बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब तक वे काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 37 महीनों से, उत्पादक मूल्य सूचकांक नकारात्मक क्षेत्र में रहा है, जिसका मूल रूप से अर्थ है कि वे लगभग मुद्रास्फीति-निरोधक परिस्थितियों में हैं।

तो $19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी आर्थिक कठिनाइयों से निकलने के लिए निर्यात करने की यह समस्या बाकी दुनिया को प्रभावित कर रही है। और आज, यदि चीन शॉक 2.0 की गंभीर चर्चा हो रही है, तो चीन शॉक 1.0 सदी के मोड़ पर हुआ था, विशेष रूप से 2001 में चीन के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के तुरंत बाद। अब, यह और भी ज़्यादा गंभीर होगा, क्योंकि चीन उन किसी भी क्षेत्र से जगह खाली नहीं कर रहा है जिन पर उसने कब्ज़ा किया हुआ है, बल्कि वह लगातार तकनीक-प्रेरित, नवाचार-प्रेरित उन्नत निर्माण में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और यह सफलतापूर्वक कर रहा है। साथी इस पर आगे चर्चा करेंगे। और यह सिर्फ विकसित अर्थव्यवस्थाओं को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि यह

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि किसी न किसी तरह यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से ऑक्सीजन खींच रहा है।

अब, एक संबंधित मुद्दा वैश्विक तकनीकी प्रतिद्वंद्विता, महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता है, और इसका ध्यान अब भू-राजनीति की बजाय भू-आर्थिक पर अधिक केंद्रित हो रहा है। यदि आप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देखें, जो 4 दिसंबर को जारी हुई थी, तो चीन के साथ आर्थिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक केंद्र बिंदु है, अब यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं रही। क्योंकि चीन भी दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता बनाए रखने की अपनी नीति पर कायम है, जबकि दूसरों को ज़्यादा निर्भर बनने के लिए बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही निर्भरता को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, अपस्ट्रीम चोक पॉइंट्स का रणनीतिक इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि हमने भारत और दूसरे देशों के मामले में रेयर अर्थ मैग्नेट के मामले में देखा।

तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएँ? हमारे पास दिशा के मामले में वास्तव में कठिन मिश्रण है, चीन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चीन अकेला नहीं है हथियार बनाकर इस्तेमाल करने के लिए, मैं इसे आपसी निर्भरता नहीं कहता, यह वास्तव में हथियारबद्ध निर्भरता है। लेकिन मैं अपनी शुरुआती बातों को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना चाहूंगा और यह कहना चाहूंगा कि मैं इस सिद्धांत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि चीन अब अपने चरम पर पहुंच गया है। चीन अपने शिखर पर नहीं है। चीन में पर्याप्त विकास गति अभी भी बाकी है। नवाचार-प्रधान विकास ऐसे विकास चालकों का पर्याप्त विकल्प नहीं होगा जैसे कि रियल एस्टेट।

लेकिन वे देख रहे हैं, वे वास्तव में नए विकास इंजन खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और चीन के रिकॉर्ड को देखते हुए, वे सफल हो सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर, यह दूसरों पर कैसे असर डालेगा।

तो मैं यहीं समाप्त करूँगा। अब मैं प्रोफेसर बिस्वजीत धर से उनके टिप्पणी के लिए अनुरोध करना चाहूँगा, जो एक बहुत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं और लंबे समय से चीन और क्षेत्रीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं।

बिस्वजीत धर: बहुत-बहुत धन्यवाद, राजदूत कांत। मुझे इस बहुत ही दिलचस्प चर्चा में बुलाने के लिए मैं आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह अत्यंत समयोचित है। धारा 4 के परामर्श के बाद बहुत कुछ कहा जाएगा, रिपोर्ट वास्तव में सामने आएगी।। हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं है। कल ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हम वास्तव में इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने भारत की रिपोर्ट के लिए किया था, जो पिछले महीने आई थी।

अब, जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी आखिरी टिप्पणियों और चीन के बारे में आपके उस बिंदु पर चर्चा करूँगा कि चीन अपनी आर्थिक गति बनाए रखेगा। मेरा कहना है कि जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, उसमें भी कुछ हद तक गति हो सकती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दशक के अंत तक विकास के संदर्भ में दिए गए कुछ आंकड़े यह सुझाव नहीं देते कि चीन किसी गंभीर संकट में होगा।

लेकिन एक और बात, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता था कि जब शी जिनपिंग पूरी 'मेकिंग चाइना' स्ट्रैटेजी लाए थे, तो उसका मकसद यह था कि 2049 तक चीन एक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बन जाएगा। तो वह लक्ष्य था। और जब हमने इसे 10 साल पहले की चीज़ के रूप में देखा, तो हम सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। और अब हम थोड़ा समझ सकते हैं कि तब क्या योजनाबद्ध किया गया था और मुझे लगता है कि यह आगे बढ़ता रहेगा और नेतृत्व द्वारा वास्तव में खोले गए नए अवसर चीन को पूरी तरह से नए क्षेत्रों में ले जाएंगे।

उदाहरण के लिए, वर्तमान में, ये सभी चर्चाएँ चल रही हैं और मैं इसे इतनी बारीकी से देख रहा हूँ कि दो प्रमुख क्षेत्रों में चीन तकनीक में भारी निवेश कर रहा है, जाहिर है, एक AI है। दूसरा, बहुत दिलचस्प रूप से, फार्मा है। इसके अलावा, जटिल अणुओं और जैविक पदार्थों में चीन का निवेश प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में बदलाव को दर्शाता है, जहाँ पहले अमेरिका और यूरोप का प्रभुत्व था। वे चीन से बहुत आगे थे। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हम चीन से कोई फार्मा दिग्गज कंपनी कितनी जल्दी देखने वाले हैं?

अब यह हमारे हित के लिए भी हानिकारक है क्योंकि हमारी विदेशी मुद्रा आमदनी के मामले में, फार्मास्यूटिकल्स भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा अर्जक है। तो आपका यह तर्क कि इसका हमें नुकसान होगा, और हम पहले ही चीन से सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री या फार्मा उद्योगों पर काफी निर्भर हैं, और हम अपने पीएलआई योजना का उपयोग करके इस निर्भरता से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर चीनी लोग जीवविज्ञान में अधिक निवेश कर रहे हैं, तो यह भारतीय उद्योग के लिए बहुत मुश्किल लगता है, और हम सब यह कहकर

गर्व करते हैं कि भारत का उद्योग दुनिया की फार्मेसी है। तो यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है।

अब, बेशक, चीन की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी पकड़ है। 2014 में, यह पीपीपी के संदर्भ में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। और बेशक, इस स्थिति को उसने बनाए रखा है। सामान्य शब्दों में, वर्तमान में चीन का आकार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगभग 63% के बराबर है। यह दशक की शुरुआत में 70% तक पहुँच गई थी, और फिर यह नीचे आ गई। और आईएमएफ का अनुमान है कि 2030 तक यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 72% होगा। इसलिए सापेक्ष विस्तार में, चीन वहां जीतता हुआ दिख रहा है।

और यह संख्या, वैश्विक विकास में चीन का योगदान 30% पर स्थिर रहा है। और कल, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी इस बात का ज़िक्र किया था कि चीन असल में ग्लोबल ग्रोथ में लगभग 30% योगदान देता है। तो यह बहुत बड़ा है। और चीन में जो कुछ भी होता है, उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किसी न किसी रूप में गंभीर असर पड़ेगा। अब, बेशक, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया, कोविड के बाद की रिकवरी के बाद से विकास धीमा रहा है। और यह भी संभव है कि यह दशक के अंत तक लगभग 5% या उससे कम ही बना रहे, जैसा कि यह भी बताया गया।

और हाँ, जैसा कि आपने कहा, आईएमएफ ने विकास के अनुमानों को अपग्रेड किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यही देखना चाहता हूँ कि आईएमएफ ने किस आधार पर अपग्रेड किया है, भले ही यह सिर्फ़ 0.2% हो, आईएमएफ ने किस आधार पर यह फ़ैसला

लिया है और यह कुछ दिनों बाद पता चलेगा। बेशक, वृद्धि हुई है, और फिर से इस तथ्य के आधार पर कि घरेलू मांग इतनी कमजोर है, अब आईएमएफ इसके बारे में बात कर रहा है और हम इसे काफी समय से सुन रहे हैं, तो फिर से यह कुछ हद तक रहस्य है कि इतनी कमजोर घरेलू मांग के बावजूद, आईएमएफ ने वास्तव में इसे कैसे उन्नत किया?

मैं वास्तव में यह उम्मीद कर रहा था कि विकास की भविष्यवाणियों को कम कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। और निश्चित रूप से संपत्ति क्षेत्र, हमने फिर उल्लेख किया कि यह अभी भी अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है और यह वास्तव में घटती हुई उपभोक्ता विश्वास का परिणाम है, जिसके कारण कमजोर खपत और मुद्रास्फीति दबाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक दोनों ही नकारात्मक क्षेत्र में हैं। तो यह मुद्रास्फीति में गिरावट का एक क्लासिक मामला है। वास्तव में चीन इस समय एक मुद्रास्फीति-मुक्त स्थिति में है और पूरे वर्ष 2025 की अगर आप मुद्रास्फीति को देखें, नवंबर तक यह वास्तव में पिछले साल के स्तर की तुलना में नकारात्मक क्षेत्र में है।

तो कुछ करना जरूरी है और फिर आपने जो बात कही, वह आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने भी कही, कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि चीन के लिए उपभोग-आधारित विकास की ओर रुख करना सर्वोच्च नीति प्राथमिकता है। तो अगर चीन गति धीमी नहीं करता है, क्योंकि निर्माण वृद्धि दर अभी भी लगभग 5% है, तो हम ऐसे स्थिति को देख रहे हैं कि चीन अंतरराष्ट्रीय बाजार का उपयोग करने जा रहा है।

अब नवंबर की शुरुआत में चीन ने वास्तव में 10 ट्रिलियन सीएनवाई का एक प्रोत्साहन पैकेज उपयोग किया, जो कि $1.5 ट्रिलियन है, और यह वित्तीय पैकेज सामान्य कर्ज को स्थिर करने और बुनियादी ढांचा खर्च को तेज करने के लिए था। यह एक पांच साल का पैकेज है जिसे उन्होंने घोषित किया है। तो यह अभी भी लागू किया जा रहा है, इसलिए हमें देखना होगा कि यह कैसे चलता है। अब वे वास्तव में उपलब्ध घाटे की जगह का सक्रिय रूप से उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि चीन में भी बहुत बड़ा वित्तीय घाटा चला रहा है, जिसका वे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करने जा रहे हैं।

अब, बेशक, चीन के पास -- सवाल यह है कि क्या चीन के पास प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त क्षमता है? यह वही सवाल है जो हम सभी पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि यह वित्तीय घाटा चला रहा है और इस साल यह जीडीपी का 8.6% है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा सुरक्षित सीमा के रूप में सुझाए गए स्तर से कहीं अधिक है। और यह 2020 में, यानी कोविड वाले साल में दर्ज किए गए स्तर से थोड़ा कम है। दूसरी बड़ी समस्या बढ़ती हुई सार्वजनिक ऋण है, जो अब जीडीपी का लगभग 90% हो गया है, और पिछले तीन सालों में, महामारी के बाद से चार सालों में, इसमें लगभग 37% की बढ़ोतरी हुई है। और बेशक, यह अमेरिका के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी दूसरे बड़े देशों की तुलना में यह बहुत ज़्यादा है।

मौद्रिक नीति पर कम से कम दो मोर्चों पर रुकावटें हैं। पहला है बहुत कमजोर युआन, जो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना को मौद्रिक नीति को आसान बनाने की गुंजाइश देता है, और दूसरा, चीनी बैंक

पहले ही कमजोर लाभप्रदता से जूझ रहे हैं, इसलिए ब्याज दरें घटाना और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना वास्तव में एक विकल्प नहीं है। और फिर, बेशक, रियल एस्टेट की समस्या है, जिसमें लगातार कम रिटर्न के बावजूद अधिक निवेश किया जा रहा है।

दूसरी समस्या जो मुझे लगता है कि चीन में अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बढ़ावा देने से रोक सकती है, वह है महंगाई का डर। मुझे भरोसा है कि वे बाइडेन के अनुभव का मूल्यांकन कर रहे हैं। कोविड के बाद बाइडेन प्रशासन के कामों में एक बड़ा स्टिमुलस पैकेज शामिल था, जिसके कारण महंगाई बढ़ी जिससे अमेरिका को निपटना काफी मुश्किल हुआ, लेकिन यह कई सालों तक बनी रही।

अब चीन, बेशक, यह नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, क्योंकि चीन, जो अपने विस्तार के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का उपयोग कर रहा है, वह इससे इतना अभ्यस्त हो चुका है, फिर भी अपनी वृद्धि की गति के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का उपयोग करता रहेगा, और वह उच्च मुद्रास्फीति के कारण अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता खोना नहीं चाहेगा। अब मुद्रास्फीति-विरोधी रुझानों से असल में चीन को फायदा हुआ है क्योंकि इससे वास्तविक विनिमय दर में काफी गिरावट आई है और इससे उन्हें निर्यात को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। आपने अभी जो कहा कि पहले 11 महीनों में व्यापार अधिशेष $1 ट्रिलियन से अधिक है, वह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि वे मंदी से लाभ उठा रहे हैं और यह मानना काफी महत्वपूर्ण है। और यह किसी एक वर्ष के लिए एक रिकॉर्ड उच्च है, जो 2024 में लगभग 992 अरब डॉलर की अधिशेष राशि से अधिक है।

अब चीन से कुल निर्यात डॉलर्स के लिहाज से पिछले साल की तुलना में लगभग 6% अधिक था और नवंबर में, अक्टूबर की तुलना में जो कमी थी, उसकी तुलना में वृद्धि हुई। मॉर्गन स्टेनली वास्तव में भविष्यवाणी करता है कि 2030 तक वैश्विक निर्यात में चीन का बाजार हिस्सा 16.5% तक पहुंच जाएगा और वर्तमान में यह 15% से कम, लगभग 14% है। और यह अत्याधुनिक निर्माण और उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, रोबोटिक्स और बैटरी द्वारा बढ़ावा मिलेगा।

अब चीन, बेशक, अमेरिकी बाजार से दूर हो गया है और बीते कुछ वर्षों में, विशेष रूप से बाइडेन के पहले कार्यकाल के बाद, यह काफी हद तक बढ़ गया है और मेरे पास जो आंकड़े हैं, वे दिखाते हैं कि यह कितना बड़ा है। 2017 में, जब ट्रंप पहली बार आए और चीन को लक्षित करना शुरू किया, तो लगभग 22% अमेरिकी आयात चीन से हुआ। आज यह 9% पर आ गया है। और 2017 में, चीन के निर्यात का 19% अमेरिका गया था। 2025 के पहले नौ महीनों में यह 10.4% पर आ गया था। इसलिए अगर आप नवंबर के आंकड़ों को देखें, हमारे पास अभी चीन के कस्टम विभाग से विस्तृत आंकड़े नहीं हैं, यह और भी कम होने वाला है, यही मैं उम्मीद करता हूं।

तो चीन अब अपनी इस क्षमता पर भरोसा कर रहा है कि वह आसानी से अपने निर्यात बाजारों को अन्य बाजारों में विविधीकृत कर सकता है। तो यह चीन के लिए एक लालच है। तो चीन को अपने घरेलू बाजार की ओर क्यों देखना चाहिए, इसे अपने घरेलू उपभोग को क्यों बढ़ावा देना चाहिए जब यह आसानी से अन्य बाजारों में जा सकता है और भारत के मामले में भी,

यह फिर से भारत में एक बड़े स्तर पर प्रवेश कर चुका है और हमारे व्यापार घाटे के मुकाबले चीन के साथ वास्तव में बहुत बढ़ गया है।

तो हम एक काफी गंभीर स्थिति में हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि चीन वही करेगा जो उससे कहा जा रहा है और इसे 2008 से कहा जा रहा है। वह पहली बार था जब अमेरिकियों ने यह महसूस किया कि उनका इतना बड़ा व्यापार घाटा है। उन्होंने अलगाव के बारे में बात की, चीनियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग होने को कहा। 2008 से 2025 तक, अलगाव का कोई वास्तविक संकेत नहीं है और यह देखना बहुत कठिन है कि भविष्य में यह कैसे होने वाला है, यह वे चीजें हैं जिनके बारे में नेतृत्व योजना बना रहा है।

तो मैं एक निराशावादी बात कहकर खत्म करूँगा कि मुझे सुरंग के आखिर में ज़्यादा रोशनी नहीं दिख रही है। इस तथ्य के बावजूद कि चीन मुश्किल में लग रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अशोक कांत: धन्यवाद, बिस्वजीत, न केवल यह स्पष्ट और गहन आकलन देने के लिए कि आज चीनी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है बल्कि यह भी कि आगे क्या होने वाला है।

संतोष कुमार: धन्यवाद, राजदूत महोदय। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आईसीडब्ल्यूए का धन्यवाद। मैं कुछ बातों पर विस्तार से बात करूंगा। मुझे लगता है कि जैसा कि राजदूत पहले ही संकेत दे चुके हैं, एक बात यह है कि आज की चीन की अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी का महत्व और इसकी भूमिका क्या है। फिर मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि उद्योग के नज़रिए से

आपूर्ति श्रृंखलाओं ने कैसे प्रतिक्रिया दी है और इन प्रतिक्रियाओं का व्यापार और निवेश प्रवाह पर क्या असर पड़ा है।

आइए प्रौद्योगिकी से शुरू करते हैं। जब चीन कहता है कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है और इसे अपनी नीति निर्माण में केंद्रीय स्थान देता है, तो मुझे लगता है कि इसके कई पहलू हैं। अगर आप इसे खोलकर देखेंगे, तो आपको कम से कम पाँच या छह अलग-अलग कारण मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इन पाँच या छह कारणों या प्रेरणाओं पर विचार करना उपयोगी होगा कि तकनीक को अर्थव्यवस्था का इतना मजबूत स्तंभ बनाने में क्या योगदान है, विशेष रूप से पिछले लगभग 10 वर्षों में। तो पहला कारण वास्तव में विदेशी तकनीक पर निर्भरता को कम करना है। मुझे लगता है कि यह दस साल पहले भी स्पष्ट था और तब से केवल बढ़ा है। इसकी ज़रूरत बढ़ गई है। और यह बात हर जगह लागू होती है, लेकिन खासकर कोर टेक्नोलॉजी में, मुझे लगता है कि चीन इसे बहुत ज़रूरी मानता है।

और ये सभी कारण जानबूझकर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर मेरी बातें दोहराई हुई लगें तो मुझे माफ़ करना, लेकिन यह सच में एक अलग नज़रिए से आ रहा है। और जब मुझे लगता है कि हम जिन भाषणों में उच्च-गुणवत्ता वाले विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि चीन जिस बात पर ज़ोर देता है, वह है प्रौद्योगिकी उत्पादन के एक कारक के तौर पर काम करना। तो पहले, जब यह मजदूरी सस्ती थी, जो उत्पादकता को बढ़ा रही थी, अब यह उत्पादन के एक कारक के रूप में प्रौद्योगिकी की ओर देख रहा है। तो यह एक और दृष्टिकोण है।

तीसरा है अग्रणी उद्योग और नई उत्पादक शक्तियाँ, जो कई, कई नीतियों, भाषणों और दस्तावेज़ों में उल्लेखित हैं। और जब वे नई उत्पादक शक्तियों की बात करते हैं, तो वास्तव में यह भविष्य के उद्योगों के अग्रणी क्षेत्रों पर कब्जा करने के बारे में है, ऐसा कह सकते हैं। और चौथा, मेरा मानना है, तकनीकी का दृष्टिकोण है शुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा। यह सैन्य आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा आदि की बात करता है।

और पाँचवाँ अधिकतर तकनीक का उपयोग वैश्विक प्रभाव के साधन के रूप में करने के बारे में है। आप इसे मानकों के लागू करने में देख सकते हैं, चीन एक बड़ा रोल चाह रहा है। तो फिर, तकनीक फिर से केंद्र में आती है। और आखिरी है, बेशक, चीन के घरेलू लक्ष्य, राष्ट्रीय पुनरुत्थान का चीनी सपना और कई अन्य, जो घरेलू राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी, एक बार फिर, इन सभी पर असर डालती है। इसलिए ये कुछ कारण हैं कि क्यों चीन में प्रौद्योगिकी नीति निर्माण के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है।

अब, जो व्यक्ति चीन के बाहर किसी देश में जैसे भारत में बैठा है, वह इसे कैसे देखता है और इसका मूल्यांकन कैसे करता है? 10 साल पहले, जब स्टेट काउंसिल द्वारा 'मेड इन चाइना 2025' नामक एक नीति की घोषणा की गई थी, तब यह बहुत उत्साह पैदा कर गया क्योंकि यह कई उद्योगों में महत्वाकांक्षा की स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। और कुछ सालों के बाद, कुछ पश्चिमी शक्तियों और अन्य कारकों की प्रतिक्रिया के कारण, भू-राजनीतिक रूप से इसे आगे बढ़ाना सुविधाजनक नहीं था। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में चीनी नीति दस्तावेजों से इस नीति के संदर्भ गायब हो गए हैं।

लेकिन अगर आप फिर भी उस रोडमैप की ओर लौटें, तो वहां 2015 में चीनी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 10 क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि 2025 को उन लक्ष्यों में से कुछ को प्राप्त करने के पहले चरण के रूप में निर्धारित किया गया था। पिछले महीने, यूएस-चाइना इकोनॉमिक और सेफ्टी कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की, जो वास्तव में 10 साल की यात्रा का विश्लेषण करती है, और मैं आप सभी से इसे पढ़ने की जोरदार सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें केवल उद्योग क्षेत्र ही नहीं बल्कि चीन द्वारा बनाई गई घटक-स्तरीय क्षमताएँ भी शामिल हैं। यह इस कार्यक्रम का एक बहुत ही विस्तृत मूल्यांकन है। तो मैं शायद सिर्फ एक मिनट यह संक्षेप में बताने में बिताऊँगा कि उन्होंने क्या पाया।

उन्होंने पाया कि लगभग तीन क्षेत्रों में, चीन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है, जो सेमीकंडक्टर्स, सीएनसी मशीनें और विमानन हैं। तो इन क्षेत्रों में, उन्होंने स्थानीयकरण, आधुनिकीकरण आदि के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन अन्य क्षेत्रों में उन्हें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। वास्तव में, रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि आम तौर पर, 'मेड इन चाइना' सफल रहा है। कुछ लक्ष्यों को तो उम्मीद से पहले ही हासिल कर लिया गया है।

नए मटीरियल एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ चीन अभी भी पीछे है। लेकिन रोबोटिक्स, कृषि मशीनरी और रेलवे जैसे क्षेत्रों में उन्हें थोड़ी सफलता मिली है। और यह इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक उपकरणों को भी प्रमुख सफलताओं के रूप में सूचीबद्ध करता है। और फिर कुछ वाइल्ड कार्ड भी हैं, जैसे कि आपने जिनका उल्लेख किया वह बायोफार्मा क्षेत्र। तो दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल BioEurope में, जो दुनिया का एक सबसे बड़ा सम्मेलन है, मंच पर एक प्लेबुक

रखी गई थी जिसमें बड़ी अमेरिकी फार्मा कंपनियां यह बता रही थीं कि उन्होंने चीन में अधिग्रहण की लहर कैसे शुरू की।

तो अगर आप रैंकिंग देखें, तो पिछले दो-तीन वर्षों में $1 बिलियन से अधिक के सभी अधिग्रहण चीन में अमेरिकी फार्मा कंपनियों द्वारा ही हुए हैं, उसी कारण से। तो शायद 10 साल पहले इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब कई वजहों से यह सामने आया है। मुझे लगता है कि क्लिनिकल ट्रायल बहुत आसान हो गए हैं, वगैरह। इसके कई कारण हैं। तो अब यह सब कैसे हुआ, तकनीकी क्षेत्र में यह 10 साल की यात्रा कैसे शुरू हुई?

कुछ अच्छे से जाने-माने कारण हैं, अच्छी तरह से अध्ययन किए गए कारण हैं, जैसे कि सब्सिडी और नीतियाँ। लेकिन इसके अलावा लंबवत एकीकरण का और अधिक सूक्ष्म खेल भी है, उद्योगों के लंबवत एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच बहुत समन्वय रहा है। बेशक, घरेलू खरीद नियम हैं जो चीनी कंपनियों के पक्ष में हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में उन्होंने विदेशी निवेशकों को चीन में तकनीक लाने के लिए बाजार तक पहुंच के बदले प्रोत्साहित भी किया है। तो प्लेबुक वास्तव में एक वैश्विक प्रकार के फार्मूले की बजाय क्षेत्रीय स्तर पर है। फिर भी, इन प्रकार के कुछ केस स्टडीज़ पढ़ना बहुत ही रोचक है।

अब मैं अपनी टिप्पणियों के अगले हिस्से की ओर बढ़ूंगा, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं पर हैं। दुनिया भर के देशों और कंपनियों के लिए, पिछले पांच वर्षों में भविष्य में निवेश करने, यह निर्णय लेने कि हमें अपना निर्माण सुविधा कहां लगानी चाहिए, के संदर्भ में स्थिति बहुत अस्थिर रही है, क्योंकि यह न केवल नीतियों के निर्माण की दृष्टि से बल्कि मांग की दृष्टि से भी बहुत अस्थिर वातावरण

रहा है। तो सप्लाई चेन चीन से दूसरी जगहों पर जाने लगी हैं, यह आंशिक रूप से हो रहा है, यह सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं फैला है, लेकिन कुल मिलाकर अगर एक लाइन में निष्कर्ष निकालना हो तो यह कहा जा सकता है कि यह सप्लाई चेन का पूरी तरह से चीन से पलायन करने की बजाय विविधीकरण ज्यादा है, तो उन्होंने विविधीकरण शुरू कर दिया है।

अब ये कुछ दिशाएँ क्या हैं? मुझे लगता है कि विविधीकरण शुल्कों से प्रेरित है, यही आज की वास्तविकता है, भू-राजनीतिक जोखिम, कुछ उद्योगों में श्रम और लागत के दबाव, बहुत सीमित क्योंकि चीन इन उद्योगों को छोड़ने नहीं दे रहा है, जो पहले एक उम्मीद थी और साथ ही लचीलापन निर्माण के लिए भी। तो कुछ उदाहरण, मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये कहानियाँ देखी होंगी, साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड को इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, लाइट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए चुना गया है।

इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी भारत ने सफलता हासिल की है क्योंकि हम अनुबंध निर्माण क्षेत्र में कम से कम दो से तीन कंपनियों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे ऑर्डर इकट्ठा करते हैं और एक प्रमुख ग्राहक पर निर्भर रहने के बजाय, वे कई ग्राहकों से ऑर्डर इकट्ठा कर पाते हैं, इसलिए यह एक सफलता की कहानी रही है। मेक्सिको ने अमेरिकी बाजार के लिए काफी आउटसोर्सिंग देखी है, यह मूल रूप से एक लॉजिस्टिक्स रणनीति है क्योंकि मेक्सिको में उत्पादन करना और अमेरिका तक भेजना आसान है। कुछ नए क्षेत्र भी उभरे हैं, जैसे कि मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप, जहां भी कुछ हद तक विविधीकरण देखा गया है।

अब इसे निवेश प्रवृत्तियों में कैसे अनुवादित किया जाता है? मुझे लगता है कि चीन में ओडीआई ने एफडीआई को लगभग दस साल पहले ही पीछे छोड़ दिया था। तो अब हम कोविड के बाद ओडीआई के और ज़्यादा फैलने का एक नया ट्रेंड देख रहे हैं क्योंकि पिछले दो सालों में एफडीआई में और गिरावट आई है, असल में नेगेटिव ग्रोथ हुई है। और मुझे लगता है कि इसके कारण अब ओडीआई वार्षिक आधार पर लगभग $50 बिलियन से $60 बिलियन का शुद्ध एफडीआई घाटा पैदा कर रहा है। तो अब हम यह देख रहे हैं कि चीन, जैसा कि टिप्पणीकार कहते हैं, मजबूती रूप से पूंजी का शुद्ध निर्यातक बनकर उभरा है। तो जिस विविधीकरण के बारे में हमने अभी बात की, उसमें चीन असल में पूंजी स्थानांतरित करने में एक बड़ा खिलाड़ी है क्योंकि सप्लाई चेन को चीन से बाहर जाना है और चीनी कंपनियाँ ऐसा कर रही हैं।

व्यापार के संबंध में, मुझे लगता है कि हमने अभी बताया कि चीन से अमेरिका के लिए होने वाले निर्यात में कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक बड़ा सवाल है कि क्या चीन से अमेरिका को होने वाला शुद्ध मूल्य संवर्धन कम हुआ है। यह अभी भी एक सवालिया निशान है क्योंकि अगर आप आसियान देशों को देखें, तो चीन के साथ व्यापार ने अब आसियान को नंबर एक पर पहुंचा दिया है, जो पहले अमेरिका के कब्जे में था, और यूरोपीय संघ स्थिर रूप से नंबर दो पर था, लेकिन अमेरिका अब तीन पर आ गया है। लेकिन चीन से आसियान के लिए कई निर्यात मध्यवर्ती उत्पाद हैं, इन्हें आसियान में उपभोग के लिए नहीं बनाया जाता।

तो सवाल यही है कि मूल्य संवर्धन के द्वारा, चीन अभी भी चीनी निर्यात की मांग में कितना योगदान दे रहा है? मुझे इसका उत्तर नहीं पता, मैं इसे बस खुला छोड़ रहा हूँ। तो शायद मैं यह बताकर बात खत्म करूँगा कि चीन के साथ भारतीय इंडस्ट्री का इंटरफ़ेस कैसा रहा है, मुझे लगता है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय उद्योग को मैग्नेट वगैरह पर निर्यात नियंत्रण का सामना करना पड़ा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र ने वास्तव में ढील के लिए काफी दबाव डाला है और जब हमारे प्रधानमंत्री गए, तो यह एजेंडा में सर्वोच्च स्थान पर था। और अब वीज़ा में राहत और सीधी उड़ानों के साथ, चीनी कंपनियां फिर से भारत में निवेश के अवसर खोजने के लिए आ रही हैं। यह कितनी हकीकत में बदलेगा, भारत-चीन आर्थिक संबंधों को कितनी स्थिरता देगा, यह अभी भी एक खुला सवाल है। इसलिए मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

अशोक कांत: बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष, वास्तव में यह पहले वाली प्रस्तुति के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खा गया। अब आपकी बारी है, अरविंद।

अरविंद सुब्रमण्यम: धन्यवाद, सर, और मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आईसीडब्ल्यूए का धन्यवाद। अगले 10 मिनट में मैं चीन की स्थानीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूँ क्योंकि जब हम 15वें पंचवर्षीय योजना की चर्चा कर रहे हैं, जब हम अर्थव्यवस्था के कुल आकार और प्रदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो चीनी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत बात प्रांतीय भूमिका है, जिसे हम स्थानीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्योंकि जब से चीन खुला है, तब से प्रांतों और स्थानीय अर्थव्यवस्था ने कुल वृद्धि को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हर प्रांत, हर क्षेत्र की अपनी जीवविकास दर और चीन की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का कारण होता है। और यही कारण है कि जब शी जिनपिंग 2035 तक के 15वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगली दो पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं जो 2049 तक जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण अन्य चर और भौतिक चर हैं। इसी को हम उपराष्ट्रीय ताकतें या स्थानीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप शायद देख चुके होंगे कि हैनान प्रान्त है जहाँ शी जिनपिंग अब तक सबसे ज्यादा छह बार गए हैं। और इसके पीछे कुछ तर्क और कुछ चिंता है। ऐसे अन्य प्रांत भी हैं जिनके बारे में शी जिनपिंग लगातार बात कर रहे हैं और उन्हें विकास की दिशा में बढ़ावा दे रहे हैं।

यदि आप इन बिंदुओं को जोड़ सकें, तो आप देख पाएंगे कि पूरी चीनी अर्थव्यवस्था और फिर केंद्रीय प्रशासन अब तटीय प्रांतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यह एक हकीकत है। क्योंकि अगर आप वर्तमान विकास दर को देखें, तो आप शीर्ष 14, 15 प्रदर्शनकर्ताओं या उन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को देखें जो चीन में प्रदर्शन कर रही हैं। संख्याओं में, हाँ, ग्वांगडोंग नंबर एक है। और संख्याओं में, जियांगसू नंबर दो है। लेकिन जब आप केवल विकास की तुलना करते हैं, तो वे वृद्धि दर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वे वास्तव में ऐसे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

और ऐसा क्यों? क्योंकि स्थानीय अर्थव्यवस्था पर राजस्व और लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में बढ़ता दबाव है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों को जोड़कर व्यापक रूप से व्याख्या करेंगे, तो आप समझेंगे कि यह केंद्रीय सरकार के लिए समस्या उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि अधिकांश रूप से, चीन में कुल सरकारी खर्च का 80% से अधिक स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाता है, 80%. और

अगर आप कहते हैं कि यदि स्थानीय सरकारें प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, प्रदर्शन के दबाव में हैं और अपने खुद के बजट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो इसका अर्थ है कि यह विकास की दिशा पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा, चाहे वह पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना हो या सोलहवीं पंचवर्षीय योजना।

और अगर आप इसे चीन में हो रहे दिलचस्प घटना से जोड़कर देखें, तो आप समझेंगे कि दो-टियर वाले प्रांत, जैसे कि हुबेई, सिचुआन और अनहुई, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी विकास दर गुआंगडोंग प्रांत से बेहतर है, जिआंगसू और सिचुआन प्रांत से भी बेहतर है। तो आप इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के दो तरीके हैं, कि इन तीन प्रांतों में ज़मीन की बिक्री ज़्यादा हो रही है जो नंबर एक की तुलना में नंबर दो पर हैं, क्योंकि गुआंगडोंग, जिआंग्सू और सिचुआन प्रांतों में बढ़ी हुई कीमतें बाज़ार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं।

और अगर आप इसे दूसरे तरीकों से करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि ग्वांगडोंग में जो विकास दर है, या शायद, उदाहरण के लिए, आप शंघाई को ही लें, शंघाई की साल-दर-साल विकास दर सिर्फ़ 1% है। अब, ये सिर्फ आंकड़े हैं। अब, जब आप प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाओं के मामले में, यह स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय सरकार पर पारंपरिक तरीके से सीधे उधार लेने पर पारंपरिक रूप से प्रतिबंध रहा है।

इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रांत तनाव में हैं क्योंकि भूमि बिक्री से होने वाली आय पर प्रतिबंध हैं क्योंकि वे गिर गए हैं। स्थानीय सरकारी वित्तीय योजनाकारों पर पहले ही बहुत ज़्यादा कर्ज़ हैं। और फिर कोविड डेटा ने राजकोषीय अंतर के संदर्भ में नकारात्मक हालात बनाए हैं। इस बारे में, लोकल सरकार केंद्र सरकार से कुछ फंड देने के लिए कह रही

है। और इसका सीधा असर पड़ने वाला है। तो 15वीं पंचवर्षीय योजना में आपको ये लक्ष्य पूरे करने हैं। आपके पास नए क्षेत्र हैं, नए लक्ष्य हैं। टेक्नोलॉजी है। बायो फार्मा है, जैसा कि संतोष ने कहा और सर ने कहा। लेकिन अब बड़ी समस्या यह है कि केंद्र सरकार को आगे आना होगा।

तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ़ केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि प्रांत अच्छा काम करें। और प्रांत अच्छा काम नहीं कर सकते क्योंकि पारंपरिक विकास दर खत्म हो गई है। तो इसके लिए नए विकास चक्र या विकल्प होने चाहिए जिनके बारे में आप बात कर सकें। इसलिए हाल के वर्षों में केंद्रीय सरकार ने स्थानीय वित्त को संभालने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। और अगर आप देखें, तो पिछले वर्ष, वर्ष 2024 में, सामान्य सार्वजनिक बजट के तहत स्थानीय सरकार को वित्तीय हस्तांतरण रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 7.4% के बराबर है। तो वे प्रांत जो वृद्धि के चालक थे, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

उसमें, जो प्रांत सबसे आगे थे, वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसलिए टियर 2 प्रांत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टियर 1 प्रांतों की मदद के लिए, केंद्र सरकार को आगे आना होगा और बॉन्ड लाने होंगे। इसका राजनीतिक अर्थ अब यह है, यह बहुत दिलचस्प है। अगर शीर्ष प्रांत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, जहाँ प्रांतीय सचिव प्रभावशाली हैं, अंदरूनी घेरे तक पहुंच रखते हैं, और तनाव में हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर एक डोमिनो प्रभाव पड़ता है। और स्थानीय राजनीतिक सामाजिककरण संरचनाओं और आत्मसात करने की प्रणालियों पर भी एक डोमिनो प्रभाव पड़ता है।

अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ बांड्स हैं जो केंद्रीय सरकार दिखा रही है। और ध्यान दें, ये सामान्य उद्देश्य वाले बांड्स नहीं हैं। ये विशेष निर्धारित बांड्स हैं। और ये आवंटित बांड हैं जो केंद्रीय सरकार प्रान्तों के लिए जारी कर रही है। यह टियर 2 है, टियर 1 नहीं, जो बुनियादी ढांचे, आपदा राहत, स्थानीय सरकार के कर्ज़ के पुनर्गठन, सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक स्थिरता के खर्च, और फिर तकनीक पर केंद्रित है। तो अगर आप वास्तव में यह समझना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि यहाँ एक और पहलू शामिल करना, स्थानीय सरकारें, जिनके पास पहले कुछ स्तर की स्वतंत्रता थी, वह स्वतंत्रता खो रही हैं क्योंकि वे केंद्रीय सरकार पर बढ़ती निर्भरता हो गई हैं।

और इसके परिणामस्वरूप, केंद्र का प्रांतों पर नियंत्रण बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे प्रांत जोड़े गए हैं, केंद्र चाहता है कि प्रांत एक खास स्तर पर काम करें। अगर इसे सही तरीके से समन्वित नहीं किया गया तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, विशेष रूप से उन प्रदर्शन लक्ष्यों के संदर्भ में, जो केंद्रीय सरकार के सामने निर्धारित किए गए हैं। तो केंद्रीय सरकार बड़ी मात्रा में ट्रेजरी बॉन्ड जारी कर रही है और इससे प्रांतों को धन जुटाने में मदद मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रांतों के लिए राजस्व के मामले में असंतुलन है।

यदि इन चीज़ों के बीच संतुलन बनाने का एक ही तरीका है, तो प्रांतों को प्रदर्शन करना होगा और प्रदर्शन करने का एक ही तरीका है कि राजस्व बढ़ाया जाए। प्रांतों के लिए राजस्व जुटाने के मामले में चार मूलभूत समस्याएँ हैं। अब आप इसे 15वें पंचवर्षीय योजना से या केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीन में एक कर संरचना है

जो काफी असंतुलित है क्योंकि यह संरचना मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है कि आपके पास मूल्य-संयुक्त कर, कॉर्पोरेट आयकर और व्यक्तिगत आयकर हैं। और अगर आप देखें, तो प्रांत अपने प्रदर्शन से खुश नहीं हैं क्योंकि रियल एस्टेट और भूमि से संबंधित करों में कमी के कारण दबाव बढ़ रहा है। यही सबसे पहला कारण है।

दूसरा, जैसा कि प्रोफेसर धर ने बताया, पीपीआई में लगातार गिरावट आ रही है और इसका प्रांतों की आमदनी पर सीधे भयानक प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि राज्यों या प्रांतों और फिर सरकारी कंपनियों द्वारा लागू किए गए टैक्स राहत के उपाय। अगली समस्या यह है। और आखिर में, प्रांतों के अंदर घरेलू निवेश असल में प्रांतों में निवेश करने के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। वे विदेशी बांड्स की तलाश कर रहे हैं, वे निवेश करने के लिए अन्य वित्तीय उत्पादों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए, घरेलू और प्रांतीय वित्तीय उत्पादों में विश्वास घट रहा है।

अब, अगर आप इस बात को देखें, तो यह बात सामने आती है कि अगर प्रांतों के बीच सही तालमेल नहीं हुआ, तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी। और असल में, जहाँ तक मैंने पढ़ा, प्रांत अपनी भूमिका को कम करके दिखा रहे हैं। दूसरे प्रांतों में एक मामला ऐसा भी था जहाँ राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। लेकिन अब, राज्य असल में इसे नहीं अपना रहे हैं। वे एक शानदार शासन चाहते हैं। और यहीं मैं रुकना चाहता हूँ। यह वर्तमान में चीन की स्थानीय आर्थिक स्थिति और परिदृश्य है। धन्यवाद।

अशोक कांत: खैर, अभी-अभी हमने उन लोगों की तीन बेहतरीन प्रस्तुतियाँ सुनीं जो इस विषय को समझते हैं, और काफी समय से चीनी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नज़र रख रहे हैं। तो मैं प्रश्नोत्तर के लिए कुछ अतिरिक्त समय लेने के लिए नूतन की अनुमति लूंगा। तो मंच खुला है। तो कृपया, आगे बढ़ें। हाँ, ठीक है। संजीव, हाँ।

अज्ञात प्रतिभागी: धन्यवाद, सर। मेरे पास प्रोफेसर धार से दो बहुत ही छोटे सवाल हैं। पहला यह कि क्या चीन की यह 'बदले में बदला' रणनीति, खासकर अमेरिका के साथ व्यापार और शुल्क के क्षेत्र में, सफल रही है या नहीं? और दूसरा यह कि आप चीन में रियल एस्टेट संकट को कितना गंभीर मानते हैं?

रवि: अपने उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए सभी वक्ताओं का धन्यवाद। मैं इस प्रश्न को संबोधित करना चाहता हूँ। वास्तव में, यह प्रश्न हमारे अध्यक्ष द्वारा पूछा गया था, यह कहकर कि, क्या इनवोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए कोई ब्रेकआउट रणनीति है, यही आपका प्रश्न था। और मेरा सवाल असल में संतोष से है कि आपने टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के जिन पांच पहलुओं का ज़िक्र किया, उन्हें आगे बढ़ाएं, जो 15वीं साल की योजना का मुख्य मुद्दा है, यानी क्या ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपग्रेड किया जा सकता है और मैन्युफैक्चरिंग अगले ऊंचे वैल्यू-एडेड लेवल पर जा सकती है?

और इस तरह, संक्षेप में कहें तो, यह होता है कि उत्पादन से ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, साथ ही ज़्यादा रोज़गार मिलता है, साथ ही ज़्यादा सैलरी मिलती है, और साथ ही ज़्यादा टैक्स

या इन चारों तत्वों का कोई संयोजन भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता बढ़ गई है और इसलिए, आप ये चीजें कर्ज बढ़ाए बिना कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए, इस क्षेत्र में मैंने जो थोड़ा पढ़ा है और इसी तरह की बातें, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य जोर उपभोग को बढ़ावा देने पर है, आदि, जैसा कि अध्यक्ष कह रहे थे, इस माध्यम से, बिना वित्तीय घाटे या अधिक कर्ज़ के जाल में फंसे हुए।

अब, यह एक जुआ है। क्या यह काम करेगा? क्या उन्नयन उस तरह का मूल्य उत्पन्न करेगा? क्या यह कर सकता है? सिद्धांत रूप में, आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, यह गणितीय रूप से संभव है। लेकिन क्या यह वास्तव में होगा? यह सवाल है और मैं इस पर आपके विचारों की सराहना करूंगा।

अशोक कांत: उस सवाल को आगे बढ़ाते हुए, रवि ने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है। संदेह पैदा हो रहा है और मुझे सच में यह समझने की काबिलियत नहीं है, हालांकि नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चीन की उपलब्धियां बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन दो अनुवर्ती विकास नहीं हो रहा है। एक, उत्पादकता धीमी बनी हुई है। उत्पादकता बढ़ नहीं रही है। और दो, नवाचार-प्रेरित वृद्धि पारंपरिक विकास चालकों, विशेष रूप से अचल संपत्ति, की जगह लेने के लिए कहीं भी पास नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं? शायद हम एक और सवाल लेंगे।

सुगंधि जे.: सभी को शुभ संध्या। मैं सुगंधी हूँ, परिषद में अनुसंधान विश्लेषक। मेरा प्रश्न श्री संतोष से है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभुत्व रखता है और जैसा कि आपने उल्लेख किया कि इसने निर्यात नियंत्रण भी सख्त किए हैं। तो,

आपको क्या लगता है कि चीन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में किस हद तक समस्या पैदा कर रहा है? धन्यवाद।

अज्ञात प्रतिभागी: धन्यवाद, सर। मेरा सवाल संतोष से है, सर। एआई आज तकनीक और अर्थव्यवस्था का एक बहुत वास्तविक हिस्सा है। तो, चीन ने जो कम लागत में एडवांस मॉडल्स जैसे डीपसीक बनाये हैं, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम इससे क्या सीख सकते हैं? और दूसरा संबंधित सवाल यह है कि आपने कहा कि चीन प्रौद्योगिकी का उपयोग उत्पादन का एक कारक के रूप में कर रहा है, खासकर घटती कार्यबल के कारण। तो, भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ है, लेकिन क्या यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा अगर चीन ऐसा करना जारी रखता है? धन्यवाद।

बिस्वजीत धर: मुझे अफ़सोस है। चीनी पहले से ही यह लड़ाई जीत रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर ज़्यादा टैरिफ लगाने में देरी कर रहे हैं, वह इसका एक संकेत हो सकता है। अब, मैं संतोष ने जो कहा था उसके मूल्य संवर्धन भाग से संबंधित इस मुद्दे पर भी बात करना चाहूँगा। लेकिन मुद्दा यह है कि, देखिए, अगर निर्यात लगभग 19% से घटकर 10% हो जाता है, तो यह एक गंभीर समस्या है। मैं आपको एक उदाहरण दूँगा। मैं वास्तव में कुछ विस्तृत संख्याओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे हमारे नजरिए से देख रहा था, मोबाइल फोन सेक्टर में क्या हो रहा है। क्योंकि हुआ यह है कि चीन ने जो भी जगह खाली की है, और चीन ने काफी जगह खाली की है, उस जगह पर हमने कब्ज़ा कर लिया था।

और अब हमारी बारी है कि हम अमेरिका से दूर जाएं। और अब हम अन्य बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि, उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य बाजार जिनमें हम प्रवेश कर रहे हैं। तो अमेरिका में कमी होने की गंभीर संभावना है। हालांकि यह अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका के सांख्यिकीविद अपने निष्कर्ष घोषित करने से बेहद डरते हैं। और उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। तो जैसे को तैसा वाली बात दोनों तरफ से काम नहीं कर रही है। ट्रंप पीछे हट रहे हैं, और यह सब। तो देखते हैं नए साल में क्या होता है।

आपका दूसरा सवाल था, मैं भूल गया। रियल एस्टेट संकट, बिल्कुल। रियल एस्टेट संकट, मुझे लगता है कि यह रहने वाला है। और रियल एस्टेट को इस संकट से निकालने के लिए जिस तरह के संसाधनों की ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार उन संसाधनों को जुटा पाएगी। क्योंकि उनके पास एक बड़ा केक है। और अगर उन्हें तकनीक में निवेश करना पड़े, अगर उन्हें वह सब कुछ करना पड़े जो वे 15वें पंचवर्षीय योजना में बात कर रहे हैं, और फिर उन्हें वास्तव में बीमार व्यक्ति को बचाना पड़े, तो यह चीन की गर्दन पर एक लगातार बोझ की तरह रहेगा। मुझे नहीं पता कि वे उससे कैसे बचेंगे।

एक बात है, मुझे यह कहने का मन हुआ क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, क्योंकि चीनी अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या उन्हें सच में, और यही बात आपने कही थी, कि क्या उन्हें सच में सही चीज़ें मिल रही हैं। मुझे याद है, करीब 10 साल पहले, चीनी पेटेंट ऑफिस दुनिया का सबसे बड़ा पेटेंट ऑफिस बन गया था। और जब आवेदनों

की संख्या लाखों में पहुँच गई, तो अमेरिकी पूरी तरह हैरान रह गए। और अब, पिछले कुछ सालों में, अगर आप लिटरेचर देखें, तो एक विरोध हो रहा है। कैसे?

विरोध हो रहा है, चीनी कमेंटेटर कह रहे हैं कि नंबर काफी नहीं हैं, आपको गुणवत्ता देखनी होगी। अब, यह इस बात का बड़ा संकेत है कि तकनीकी विकास के मामले में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें तकनीकी क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसका सच में अध्ययन करने की ज़रूरत है।

संतोष कुमार: धन्यवाद, प्रोफेसर। मैं सबसे पहले अपग्रेडेशन और मुनाफ़े वाले हिस्से पर रवि के सवाल का जवाब दूँगा। मैं सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि इन सभी तकनीकी विकास से मुनाफ़ा हुआ है क्योंकि चीनी उद्योग सच में बहुत बुरी हालत में है। प्राइवेट, स्टेट, लोकल, ग्लोबल, डोमेस्टिक, प्योर प्ले, सभी तरह की कंपनियाँ। लाभप्रदता अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। वे सच में लाभप्रदता को लेकर चुनौती का सामना कर रहे हैं।

अब, कर्ज़ वाले हिस्से की बात करें तो, अगर आप कैपिटल मार्केट ट्रेंड को देखें, तो कोविड के बाद पिछले तीन सालों में जब स्टॉक मार्केट खुले, तो हॉन्ग कॉन्ग, शेन्ज़ेन और शंघाई लिस्टिंग कुछ खास इंडस्ट्रीज़ की तरफ साफ झुकाव दिखा रही हैं, जो सभी इस एमआईसी 2025 लिस्ट में हैं, जैसे मेडिकल डिवाइस और बायोफार्मा और ये सब। तो, एक गैर-अर्थशास्त्री के रूप में मेरा निष्कर्ष यह है कि तकनीक को लागू करते समय ऋण पर निर्भरता बहुत कम होती है क्योंकि आपने जो कहा वह सही है, यह सीधे तौर पर लाभप्रदता में परिवर्तित नहीं होता। इसलिए,

यह अधिकतर पूंजी बाजारों, इक्विटी पूंजी का उपयोग है जो कुछ इस तकनीकी उन्नयन के लिए किया जा रहा है।

तो, यह एक हेज़ है। बैंक अपने आप इतनी मात्रा में ऋण नहीं दे रहे हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था को वित्तपोषित कर सकें। वे कहानी को थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए थोड़ा ऋण दे सकते हैं और फिर आईपीओ के लिए जाते हैं और पूंजी जुटाते हैं। यह मेरी समझ है। और मैं फिर से सोचता हूँ जो राजदूत ने भी कहा, यह प्रतिस्थापन नहीं कर रहा है क्योंकि तकनीक का प्रसार सबसे पहले सभी जगह समान रूप से नहीं होता। यह बहुत चयनात्मक है क्योंकि यह केवल कुछ कंपनियों में ही होता है जो कुछ विशेष क्षेत्रों में उस तरह की पूंजी का उपयोग करके ये मशीनें खरीद रही हैं, क्योंकि चीन में ज़्यादातर लघु और मध्यम उद्यमों के लिए श्रम का इस्तेमाल करना अभी भी आसान है बजाय केवल इसलिए कि कोई रोबोट उपलब्ध है, उन्नयन करने के। मुझे नहीं लगता कि यह अब तक उस हद तक पहुँच पाया है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ विभिन्न कारणों से एक बहुत ही धीमा प्रभाव होगा। तो मुझे लगता है कि यही मेरी राय है।

क्रिटिकल मिनरल्स से क्या समस्या हो रही है? मुझे लगता है कि यह सप्लाई चेन में लगातार रुकावटें पैदा कर रहा है। इन्वेंटरी लेवल बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी चीन से इन इंपोर्ट पर निर्भर हैं, वे इन्वेंटरी बढ़ा रहे हैं क्योंकि स्थिति अनिश्चित है। और निर्यात नियंत्रण तंत्र के बारे में, मुझे लगता है कि इसका वास्तविक खतरा सिर्फ महत्वपूर्ण खनिजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में इसे किन चीजों के लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि जो नौकरशाही

निर्यात नियंत्रण आदेशों का समर्थन कर रही है वह काफी व्यापक है। वे कारखानों का नक्शा बना रहे हैं, वे देशों का नक्शा बना रहे हैं, उन निर्माण स्थलों का अंतिम उपयोग का नक्शा बना रहे हैं।

तो यह क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर का इस्तेमाल है। अगर इसे अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है तो यह एक बड़ी चिंता है। महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में, मेरा मानना है कि कई देश, भारत सहित, उत्पादन को सब्सिडी दे रहे हैं और इसी तरह, लेकिन यह एक बहुत ही प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। पहाड़ियों को ब्लीच करना और महत्वपूर्ण खनिज निकालना बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला काम है। इसलिए कुछ प्राकृतिक सीमाएँ होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं।

मुझे आखिरी सवाल पसंद आया, एआई। वास्तव में, काई फंग ली, जिन्हें कई मायनों में एआई का पिता माना जाता है, ने कल फाइनेंशियल टाइम्स में एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि चीन ने एंड्रॉइड रणनीति अपनाई है, जिसका मतलब है कि वे ओपन सोर्स एआई के साथ 70% बाजार हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एंड्रॉइड फोन ने मोबाइल फोन उद्योग में 70% बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी, जबकि एप्पल छोटे हिस्सेदारी के साथ फंस गया है क्योंकि उनके पास बंद इकोसिस्टम है।

तो मुझे लगता है कि अगर आप उस लॉजिक से चलें, तो भारत के लिए सबक, मुझे लगता है कि यही आपका सवाल था, यह है कि क्योंकि हम एक बड़ा बाजार हैं, इसलिए हमें देर-सवेर अपने फैसले लेने ही होंगे क्योंकि पश्चिमी एआई मॉडल ओपन सोर्स नहीं हैं। उनमें ज़्यादा बदलाव और छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता, लेकिन चीनी सोर्स को अपनाना बहुत

लुभावना लगता है। डिपसीक बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। तो भारत के लिए असली विकल्प यह है कि क्या हम अपना खुद का मॉडल विकसित कर सकते हैं जो ओपन सोर्स हो लेकिन सुरक्षित भी हो।

यह डीपसीक से भी इंडिपेंडेंट है। क्योंकि आज अगर आप भारत में बैठे कोई इनोवेटर हैं, तो यह बहुत लुभावना है कि डीपसीक ओपन-सोर्स है, तो उसके एल्गोरिदम लेकर अपने डेटा का इस्तेमाल करके उसे डेवलप किया जाए। यह बहुत लुभावना है। तो यही असली चुनौती है। मुझे लगता है कि एआई में लड़ाई की लाइनें अब कमोबेश तय हो गई हैं, कि यह इसी तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन भारत को अभी भी एक तरह से फैसला लेना बाकी है।

पीटीसी, आखिर में, मुझे लगता है कि प्रोफेसर धर ने एक बहुत अच्छी बात कही। मैं पीटीसी तर्क में एक और पहलू जोड़ूंगा, कि आज चीन खुद सिर्फ चीन-आधारित फाइलिंग को इनोवेशन की वैलिड पहचान मानने से इनकार करता है। यह चीनी कंपनियों और चीन में काम करने वाली विदेशी कंपनियों दोनों को चीन के बाहर अपने पेटेंट रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि यह साबित हो सके कि उनके पास सच में कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि अब यह एक अच्छी तरह से शोध किया गया क्षेत्र है, कि पेटेंट की संख्या देखने के बजाय उनकी गुणवत्ता देखना ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।

अरविंद सुब्रमण्यम: धन्यवाद, चेयरपर्सन। संक्षेप में, 1994-95 से त्सुरोंगची के फाइनेंशियल डिवीज़न में बदलाव के बाद से हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो फिर असल में क्या बदला है? वहीं केंद्रीय सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा एक हस्तक्षेप किया गया है, जहां मैं उद्यमों के बारे में भी बात करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जो समृद्ध प्रांत थे, जो 1994-'95 से वित्तीय विभाजन के उलटफेर से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, उन्होंने केंद्र के खिलाफ संघर्ष नहीं किया क्योंकि उन्हें विकास करते रहने दिया गया था। इसलिए कोई समस्या नहीं हुई।

इस समस्या को तब समझा या महसूस किया गया जब इन प्रांतों को विपरीत हवा का सामना करना पड़ा। और यहीं उन्होंने महसूस किया कि एक समस्या है। तो जैसे संतोष ने एंड्रॉइड मॉडल के बारे में बात की, वैसे ही एक नया मॉडल है जिसे केंद्रीय सरकारें लागू कर रही हैं। इसे वे शर्तीय मदद कहते हैं। वे किसी कंपनी या प्रांत को पूरी तरह से बचाने के लिए यहाँ बाहर नहीं आएंगे। वे यह नहीं कर सकते। हाँ, प्रांतों के पास नकदी की कमी है, लेकिन उनके पास ये बॉन्ड हैं। उनके पास ये उद्यम हैं जिसमें वे और अधिक निवेश कर सकते हैं।

और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होता है वह यह है कि ब्याज दरों को कम करने के अलावा, वे प्रान्त, जो योजनाओं, पांच साल की योजनाओं या परियोजनाओं के साथ संरेखित हो रहे हैं, दबाव को कम करने के लिए संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करते हैं। तो यह प्रांतों पर निर्भर है कि वे उस वित्तीय दबाव को कम करने के लिए कोई पहुँच, तरीका या साधन अपनाएँ। लेकिन संरचनात्मक रूप से, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यह परिवर्तन केवल केंद्रीय सरकार द्वारा एक प्रावधान देने से

हो रहा है, जिसमें स्थानीय सरकार के लिए एक प्रावधान बनाया जा रहा है जहां वे ऋण या कर्ज को केंद्रीय सरकार के बांड के साथ बदल सकते हैं। मेरा मतलब है, यह एक बहुत अनोखा तरीका है जिसमें केंद्रीय सरकार मदद और विस्तार कर रही है।

अशोक कांत: काश हम सवालों का एक और राउंड ले पाते। बदकिस्मती से, हमारे पास सच में समय खत्म हो गया है। इसलिए, उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ जो सवाल पूछना चाहते थे। मैं इसे संक्षेप में बताने की कोशिश नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिससे इतने सारे मुद्दे और सवाल सामने आए हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं। दरअसल, किसी ने भी जवाब नहीं दिया है। और श्री शी जिनपिंग के पास उन सवालों के जवाब नहीं हैं। लेकिन ये ऐसे रुझान हैं जो हम पर गंभीर रूप से प्रभाव डालने वाले हैं।

मुझे लगता है कि इसीलिए नूतन ने आयोजन करके एक अच्छी पहल की। शायद हमें और ज़्यादा फॉलो-अप चर्चाएँ करनी चाहिए, जहाँ हम असल में चीनी अर्थव्यवस्था पर आधे दिन की वर्कशॉप कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, और कई सवाल उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए, तकनीक, क्या अच्छी हुई है, क्या अच्छी नहीं हुई है, क्या कम पड़ रहा है। तो हम इस संवाद को जारी रखेंगे। बस यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद।

टेशु सिंह: धन्यवाद सर। इस चर्चा के बाद, हम निस्संदेह चीनी अर्थव्यवस्था में हो रहे विकास और उनके व्यापक प्रभावों के बारे में काफी अधिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं।W इसके साथ ही हम पैनल चर्चा समाप्त करते हैं। मैं सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का पैनल चर्चा के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं आईसीडब्ल्यूए के कार्यकारी महानिदेशक, अनुसंधान निदेशक, आईटी

टीम, अनुसंधान संकाय और आईसीडब्ल्यूए के पूरे स्टाफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूं। आईसीडब्ल्यूए के शोध, कार्यक्रमों और आउटरीच प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल पर जाएँ। अब मैं आप सभी को हाई टी के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। एक बार फिर धन्यवाद।

-x-x-x-x-x-